

24
12.000

संख्या-1125/XIX-1/17-07/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2017
विषय- उत्तराखण्ड राज्य के एलपीजी विहीन परिवारों को गैस कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य के सभी परिवारों की रसोई को धुआं मुक्त करने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-744/2017 के क्रम में केन्द्र की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की भांति राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे परिवार, जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की तर्ज पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से आच्छादित करने का प्रयास किया जायेगा, तदोपरान्त छोटे हुए ऐसे अन्त्योदय/प्राथमिक (पी०एच०एच०) कार्ड धारक तथा रू०-2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले राशन कार्ड धारक परिवारों की पात्रता सूची तैयार कर प्रस्ताव आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) किसी भी परिवार में महिला अथवा पुरुष मुखिया अथवा किसी अन्य सदस्य के नाम पूर्व से गैस कनेक्शन होने की स्थिति में उक्त परिवार निःशुल्क गैस कनेक्शन हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) गैस सब्सिडी का दुरुपयोग न हो इस हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित राशन कार्ड धारक परिवार की महिला तथा पुरुष सदस्य का आधार नम्बर तथा बैंक खाता (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) से लिंक किया जा चुका हो।

(4) प्रस्तावित गैस कनेक्शन प्रथमतः परिवार के महिला मुखिया सदस्य के नाम से दिया जायेगा, परिवार में महिला मुखिया सदस्य के न होने की स्थिति में परिवार के ही अन्य महिला सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन दिया जायेगा। परिवार में महिला सदस्य के उपलब्ध न होने की स्थिति में वरिष्ठतम पुरुष सदस्य के नाम कनेक्शन दिया जायेगा। इस हेतु उज्ज्वला योजना की तर्ज पर प्रति कनेक्शन रु0-1600 की धनराशि ऑयल कम्पनी को दिया जायेगा, अवशेष व्ययभार लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(5) योजना चरणबद्ध रूप से संचालित की जायेगी अर्थात् प्रथम चरण में अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों को गैस कनेक्शन से संतृप्त किया जायेगा, समस्त जिलाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि उनके जिले में कोई भी अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार प्रथम चरण में गैस कनेक्शन से वंचित न हो।

द्वितीय चरण में ऐसे परिवार, जिनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्य कोई राशन कार्ड है अथवा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत अद्यावधिक बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज है, उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा, अर्थात् प्राथमिक परिवार (पी0एच0एच0) कार्ड धारक एवं बी0पी0एल0 परिवारों को सम्मिलित किया जायेगा तथा अन्तिम चरण में ऐसे कार्ड धारकों को जिनकी कुल वार्षिक आय रु0 2.50 लाख से कम है, को भी लाभान्वित किया जायेगा।

(6) यदि राज्य में गैस विहीन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य में मिट्टी तेल का आवंटन धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है। अतः राज्य में उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु घरेलू गैस विहीन परिवारों के चयन तथा गैस कनेक्शन वितरण हेतु जनपद स्तर में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी, ऑयल कम्पनी के प्रतिनिधि एवं यदि आवश्यक हो तो अन्य विभागों का सहयोग लेते हुए पात्र लाभार्थियों के सर्वे के कार्य को समयबद्ध रूप से 2 माह के भीतर अभियान के रूप में चलाया जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-152 मतदेय /XXVII(5)/2017-18 दिनांक-30.10.2017 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(8) अतः प्रकरण में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

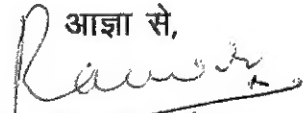
भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1125/XIX-1/17-07/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, ऑबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- मुख्य निजी सचिव, मा0 खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 6- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8- गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-05 उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 10- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
- 11- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
- 12- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की जिला हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी राजपत्र (गजट) में 200 प्रतियां प्रकाशित कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।